

[2025] 6 एस.सी.आर. 291 : 2025 आई.एन.एस.सी 662

हरप्रीत सिंह तलवार @ कबीर तलवार

बनाम

गुजरात राज्य राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

(आपराधिक अपील संख्या 2570/2025)

13 मई 2025

[सूर्यकांत* और नॉगमेईकापम कोटिस्वर सिंह, जे.जे.]

विचारार्थ मुद्दा

चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता नियमित जमानत का हकदार है।

हेडनोट्स[†]

जमानत - स्वापक औषधि और मनप्रावी पदार्थ अधिनियम:, 1985- ss.8(c), 21(c), 23(c), 29- गैरकानूनी गतिविधियाँ अधिनियम (रोकथाम), 1967-ss.17, 18, 22C - दंड संहिता,, 1860- s.120B - नारकोटिक्स की क्रॉसबॉर्डर स्मगलिंग - गुजरात के ज़रिए भारत में इम्पोर्ट किए गए 2,988. 21kg हेरोइन वाले टैल्क स्टोन की ज़ब्ती, कमर्शियल कंसाइनमेंट की आइ में, कथित तौर पर अफ़गानिस्तान से शुरू होकर ईरान के रास्ते लाई गई - अपील करने वाले ने कथित तौर पर इसे आसान बनाने में सेंट्रल और कोऑर्डिनेटिंग रोल निभाया - जमानत नामंज़ूर:

अभिनिर्धारित किया गया: दुबई में एक प्रमुख विदेशी आरोपी के साथ अपीलकर्ता की कथित बैठकें; एक चिह्नित खेप की निकासी के लिए बिचौलियों द्वारा से दस्तावेजों का हस्तांतरण; पूर्वव्यापी रूप से चालान बनाने और दूसरों को जिम्मेदारी सौंपने के प्रयास; लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करने के लिए कथित रूप से उससे जुड़ी कई फर्मों का उपयोग; और कुछ सह-साजिशकर्ताओं को उसकी टेलीफोन कॉल, संरक्षित गवाहों के बयानों और परिस्थितिजन्य संबंधों द्वारा समर्थित, अपीलकर्ता की मिलीभुगत के बारे में प्रथमदृष्टया संतुष्टि की सीमा को पूरा करती है- अभियोजन पक्ष का दावा है कि संबंधित खेप में जब्ती सबसे बड़ी हेरोइन का हिस्सा है। भारतीय इतिहास का भंडाफोड़-एन. आई. ए. अदालत के समक्ष मुकदमा चल रहा है और अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच के चरण में है-

* लेखक

कई प्रमुख गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है- 24 सबसे कमजोर या भौतिक गवाहों में से दो की मृत्यु हो गई है और दो अन्य का पता नहीं चल पाया है- गवाहों के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ का खतरा है। उन्मूलन इस स्तर पर जमानत देने के खिलाफ विद्रोह करता है- साथ ही, अपीलकर्ता के पूर्व आचरण और प्रोफाइल को देखते हुए पलायन जोखिम की संभावना है- अपीलकर्ता इस स्तर पर नियमित जमानत का हकदार नहीं है। [पैरा 27,29,30,32,35]

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967-s.43D (5)- दायरा और अनुप्रयोग- भारत का संविधान- अनुच्छेद 21- चर्चा।

[पैरा 23, 24]

उद्धृत केस लॉ:

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब [2021] 1 SCR 443 : (2021) 3 SCC 713 – का उल्लेख किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

सूचक शब्दों की सूची

2,988.21 किलोग्राम हेरोइन युक्त टैल्क पत्थरों की जब्ती; टैल्क पाउडर के रूप में छुपाए गए मादक पदार्थ; बहु-क्षेत्राधिकार मादक पदार्थों की तस्करी अभियान; मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी; अंतर-राष्ट्रीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क; मुंद्रा बंदरगाह, गुजरात; अफगानिस्तान स्थित सिंडिकेट्स; ईरान; आपराधिक साजिश; अंतरराष्ट्रीय तस्करी अभियान; नियमित जमानत; टैल्क के रूप में छिपे हुए मादक पदार्थों का आयात; सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी; भारत में हेरोइन का आयात; आतंकवादी वित्तपोषण; उड़ान जोखिम।

मामला सामने आ रहा है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 2570/2025

अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट के 28.03.2024 के फैसले और आदेश से, CRA नंबर 1980/2023 में।

दलों के लिए उपस्थिति

अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए:

सीए सुंदरम, सिद्धार्थ भटनागर, डॉ. आदित्य सोंधी, वरिष्ठ अधिवक्ता, निपुण कत्याल, नम्बूदिरी प्रसन्ना, धनंजय कुमार, नदीम अफरोज, मनन शर्मा, सुश्री रोहिणी मूसा, रिजुक सरकार, सुश्री निधि श्री बी. वी.

अधिवक्ता प्रत्यर्थी के लिए:

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सुश्री राधिका मिश्रा, सुश्री शिविका मेहेरा, रजत नायर, संदीप के. सदावर्ते, सुश्री जीनत मलिक, सुश्री तन्वी दुबे, आदित्य शंकर दीक्षित, राजेंद्र सिंह राणा, सार्थक करोल, अरविंद कुमार शर्मा।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

सूर्यकांत, जे.

अनुमति दी गयी।

2. अपीलकर्ता अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट (हाई कोर्ट) द्वारा 28.03.2024 को दिए गए आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज FIR नंबर RC-26/2021/NIA/DLI दिनांक 23.09.2022 (FIR) के संबंध में उसकी रेगुलर बेल की याचिका खारिज कर दी गई है।
3. उपरोक्त प्राथमिकी आर. घरेलू संचालकों के साथ संबंध रखने वाले अफ़ग़ान-आधारित सिंडिकेट्स द्वारा कथित रूप से निष्पादित एक बहु-क्षेत्राधिकार वाले मादक पदार्थों की तस्करी अभियान की जांच से उत्पन्न होती है, जिसमें वाणिज्यिक खेपों की आड़ में अवैध रूप से भारत में बड़ी मात्रा में हेरोइन लाई गई थी।
4. इस मामले में अपीलकर्ता को आरोपी संख्या 24 के तौर पर पेश किया गया है और वह 24.08.2022 से हिरासत में है। उसके खिलाफ कथित अपराधों में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की खंड 8 (सी), 21 (सी), 23 (सी) और 29, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की खंड 17, 18 और 22 सी और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की खंड 120 बी के तहत अपराध शामिल हैं। मुकदमा वर्तमान में विशेष अदालत (एन. आई. ए.), अहमदाबाद (एन. आई. ए. अदालत) के समक्ष चल रहा है और अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ के चरण में है।
5. इस मामले के गुण-दोषों पर गौर करने से पहले, हम अपीलकर्ता, अर्थात् गुरप्रीत सिंह तलवार @ कबीर तलवार, के बारे में संक्षेप में जानकारी दे सकते हैं।
6. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता यह है कि उसने मैसर्स मैजेन्ट इंडिया नामक एक फर्म की आड़ में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह द्वारा से दिसंबर 2020 में भारत में आयातित हेरोइन युक्त टैल्क पत्थरों की खेप की सुविधा में केंद्रीय और समन्वयात्मक भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्तमान अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता को अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगी संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

7. यह मामला तब सामने आया जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), गांधीधाम यूनिट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस नंबर DRI/AZU/GRU/NDPS-01/2021 रजिस्टर किया। यह मामला 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन की ज़ब्ती से जुड़ा है, जो कथित तौर पर अफगानिस्तान से आई थी और ईरान के बंदर अब्बास के रास्ते लाई गई थी। एक मेसर्स आशी ट्रेडिंग कंपनी को संबोधित एक खेप में टैल्क पाउडर के रूप में छिपाकर नशीले पदार्थों की तस्करी भारत में की गई थी।
8. खुफिया जानकारी और सीमा शुल्क अधिकारियों और डी. आर. आई. द्वारा समानांतर जांच के आधार पर, मामले को अंततः एन. आई. ए. ने अपने हाथ में ले लिया। एनडीपीएस अधिनियम और यूएपीए के तहत 06.10.2021 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कथित अपराध के प्रसार और परिमाण के कारण, जांच के प्रयास बढ़े, जिसके कारण एन. आई. ए. को मादक पदार्थों की इसी तरह की सीमा पार तस्करी में अपीलकर्ता की संलिप्तता का पता चला।
9. एन. आई. ए. इस प्रकार आरोप लगाता है कि सितंबर 2020 में, अपीलकर्ता ने दुबई का दौरा किया, जहाँ उसका परिचय एक सनी कक्कड़ द्वारा एक विदेशी नागरिक और एक नामित आरोपी (डब्ल्यू. ए.-7), जो कथित रूप से एक अंतरराष्ट्रीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क के शीर्ष पर था, के साथ हुआ।
10. इस प्रारंभिक बैठक ने, संरक्षित गवाहों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम और यूएपीए के तहत दर्ज किए गए बयानों के अनुसार, एक 'आपराधिक साजिश' की नींव रखी, जिसमें अपीलकर्ता वैध वाणिज्यिक वस्तुओं की आड़ में भारत में हेरोइन के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत हुआ। कहा जाता है कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता ने अपने लेखाकार, सुनील जैन को अपने कर्मचारी और घरेलू सहायक, प्रिंस शर्मा (ए-25) के नाम पर एक स्वामित्व संस्था के पंजीकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। यह इकाई-मेसर्स मैजेन्ट इंडिया-22.09.2020 को पंजीकृत थी, और अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता के प्रभावी नियंत्रण में रही।
11. इसके बाद, अपीलकर्ता पर आरोप है कि उसने दूसरी बार दुबई की यात्रा की, जिसमें उसने राजू दुबई के साथ आयात के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया। इसके तुरंत बाद, 21,880 किलोग्राम वजन वाले सेमी-प्रोसेस्ड टैल्क के 22 बैग का एक कंसाइनमेंट 16.11.2020 को M/s हबीब शबाब टैल्क एंड मार्बल प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड, अफगानिस्तान द्वारा भेजा गया, और इसे बंदर अब्बास पोर्ट, ईरान के रास्ते M/s मैजेंट इंडिया को भेजा गया।
12. यह खेप प्रवेश पत्र संख्या 2083348 के माध्यम से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 23.12.2020 को पहुंची। कहा जाता है कि इस समय के आसपास, राजू दुबई के एक ज्ञात सहयोगी के रूप में वर्णित अमित शर्मा पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली में अपीलकर्ता

के कार्यालय गए थे। सुनील जैन और संरक्षित गवाहों के बयानों के अनुसार, अमित शर्मा को अपीलकर्ता के प्रत्यक्ष निर्देश के तहत जीएसटी और आईईसी प्रमाण पत्रों सहित फर्म के आयात दस्तावेज सौंपे गए थे। खेप की निकासी बाद में पूरी की गई, हालांकि इसे 100% परीक्षा के लिए चिह्नित किया गया था।

13. महत्वपूर्ण रूप से, मैसर्स मैजेन्ट इंडिया द्वारा अफगान आपूर्तिकर्ता को कोई प्रेषण नहीं किया गया था। इसके बजाय, NIA का आरोप है कि अपीलकर्ता को उसके द्वारा कंट्रोल की जाने वाली दूसरी फर्मों के ज़रिए बार्टर कंपनसेशन के तौर पर परफ्यूम, ड्राई फ्रूट्स और जूते-चप्पल मिले। कथित तौर पर, सामान दुबई के माध्यम से भेजे गए, बिना कोई कस्टम ड्यूटी का भुगतान किए, और इन्हें ऐसी संस्थाओं के माध्यम से निपटाया गया, जिनका अपीलकर्ता के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व संबंध था।
14. जब प्रवर्तन एजेंसियों ने 2021 की शुरुआत में इसी तरह की खेपों की जांच शुरू की, तो कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रिंस शर्मा और अमित शर्मा ने भाग लिया। संरक्षित गवाहों में से एक के अनुसार, अपीलकर्ता ने अमित शर्मा को खेप की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए एक पिछली तारीख के 'प्राधिकरण पत्र' पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने निर्देश दिया कि उसकी पत्नी शैली तलवार से जुड़ी कंपनी मेसर्स प्रभ इंटरनेशनल को माल की बिक्री दिखाने के लिए काल्पनिक चालान पेश किए जाएं। हालांकि, माल की कोई वास्तविक आवाजाही कभी नहीं हुई; लेन-देन केवल कागजों तक ही सीमित था।
15. एन. आई. ए. द्वारा 24.08.2022 को अपीलकर्ता के आवास की तलाशी ली गई और संपत्ति के दस्तावेज, आयात-निर्यात रिकॉर्ड और कथित रूप से संबंधित अवधि के दौरान उपयोग किए गए आई. फोन 13 प्रो सहित कई वस्तुओं को जब्त किया गया। उसी दिन उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। कॉल विवरण रिकॉर्ड की बाद की फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि मुंद्रा में खेप की मंजूरी के दौरान, अपीलकर्ता, अमित शर्मा और राजू दुबई के बीच एक ही समय पर संपर्क था, जो एक ही मोबाइल टावर क्षेत्र के भीतर स्थित थे।
16. 14.03.2022 को दायर पहले आरोप पत्र में, अपीलकर्ता को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था। हालांकि, इसके बाद 20.02.2023 को दूसरी अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल की गई, जिसमें अपीलकर्ता को औपचारिक रूप से अभियुक्त संख्या-24 के रूप में नामित किया गया। उस पर IPC की धारा 120B, NDPS एक्ट की धारा 8(c), 21(c), 23(c), 29 और UAPA की धारा 17, 18, 22 C के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने कई संरक्षित गवाहों के बयानों का भी हवाला दिया, जिनमें वे पूर्व कर्मचारी और सहयोगी शामिल थे, जिन्होंने कथित रूप से मजेंट इंडिया

के गठन और नियंत्रण में अपीलकर्ता की भूमिका की पुष्टि की, अर्थात्, आयात की रसद, और छिपाने के लिए एक कागजी निशान बनाने के बाद के प्रयास।

17. अपीलकर्ता ने पहले विशेष अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 30.07.2023 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया, यह मानते हुए कि रिकॉर्ड पर विषय-वस्तु एनडीपीएस अधिनियम और यूएपीए के तहत साजिश के प्रथमदृष्टया मामले का खुलासा करती है। विशेष न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, तस्करी अभियान की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और अपीलकर्ता द्वारा चल रही जांच और मुकदमे के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना पर भी ध्यान दें।
18. इसके बाद पीड़ित अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी. आर. पी. सी.) की खंड 439 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, 28.03.2024 के एक तर्कपूर्ण आदेश से, उच्च न्यायालय ने इसी तरह अपीलकर्ता की नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले के तथ्यों में यू. ए. पी. ए. की धारा 43D(5) के तहत कानूनी रोक लागू होती है। इसने आगे कहा कि अपीलकर्ता की भूमिका, जिसे साजिश की प्रकृति और प्रमुख गवाहों के बयानों के साथ समग्र रूप से देखा जाता है, उस स्तर पर निरंतर हिरासत की गारंटी देती है।
19. नतीजतन, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष है। नोटिस जारी होने पर, इस न्यायालय ने समय-समय पर चल रहे मुकदमे के त्वरित संचालन को सुविधाजनक बनाने की मांग की है, केवल गुण-दोष के आधार पर जमानत के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना पर उचित और सूचित विचार को सक्षम करने के उद्देश्य से। उस संदर्भ में, एन. आई. ए. को कमजोर और भौतिक गवाहों की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था, जिनकी गवाही इस स्तर पर आवश्यक मानी गई थी। इस तरह के निर्देशों के अनुसार, एन. आई. ए. ने 24 ऐसे गवाहों की पहचान की, जिनमें से 20 से पूछताछ की गई है, जबकि दो दुर्भाग्य से समाप्त हो गए हैं, और शेष दो एजेंसी के बताए गए प्रयासों के बावजूद लापता हैं।
20. उन सीमित तथ्यों और परिस्थितियों को छूने के बाद जो हमारे विचार के लिए प्रासंगिक हैं, हम वर्तमान में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं।
21. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुएवरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी.ए. सुंदरम, श्री सिद्धार्थ भटनागर और डॉ. आदित्य सौंधी ने अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार करने वाले आक्षेपित आदेश की वैधता के खिलाफ कई दलीलें दी हैं:
 - (i) अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पूरी तरह से परिस्थितिजन्य विषय-वस्तु पर निर्भर करते हैं, और अब तक की जांच या परीक्षण कार्यवाही के दौरान उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष, प्राथमिक या यहां तक कि विश्वसनीय अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी पेश नहीं

किया गया है।

- (ii) हालांकि 20 कमज़ोर गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपीलकर्ता को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया है, और ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जो उसे किसी ऐसे खेप से जोड़ता हो जिसमें असल में गैर-कानूनी सामान मिला था;
- (iii) अपीलकर्ता से जुड़ी एकमात्र खेप मैसर्स मैजेन्ट इंडिया द्वारा आयात की गई थी, जिसे 23.12.2020 पर प्राप्त किया गया था, जिसे अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले अर्ध-संसाधित टैल्क पत्थर के रूप में घोषित किया गया था, और सीमा शुल्क अधिकारी (PW10) के बयान के अनुसार 100% निरीक्षण के अधीन होने के बाद सीमा शुल्क द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी।
- (iv) अभियोजन पक्ष के अपराध के सिद्धांत का निर्माण 'रिवर्स इंजीनियरिंग' के आधार पर किया जाता है, जो अपीलकर्ता के आयात के लगभग एक साल बाद सितंबर 2021 में पाई गई बाद की खेप पर निर्भर करता है, जिसे कथित रूप से एक अलग आरोपी से जुड़े गोदाम से बरामद किया गया था।
- (v) अपीलकर्ता को उसकी खेप को मंजूरी दिए जाने के लंबे समय बाद गोदाम में पाई गई विषय-वस्तु के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से जब एक ही चैनल या गोदाम का उपयोग करने वाले अन्य आयातकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी, जैसे कि मैसर्स व्योम फैशन और मैसर्स वीके एंटरप्राइजेज;
- (vi) आयातित वस्तुओं जैसे इत्र और ड्राई फ्रूट्स से संबंधित वस्तु विनिमय के आरोप निराधार हैं और संबंधित गवाह (X3) ने स्वीकार किया कि वस्तुओं का आदान-प्रदान दस्तावेज़ीकरण तक सीमित था और उत्पाद वास्तव में कभी नहीं पहुंचे;
- (vii) अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त राजू दुबई के बीच पाँच टेलीफोन कॉल का आरोप आपराधिक साजिश स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि राजू दुबई के साथ उसकी कथित बातचीत खराब निर्णय को प्रतिबिंबित कर सकती है, लेकिन यह स्वचालित रूप से दोषी नहीं हो सकती है, खासकर जब कोई फॉरेंसिक लिंक या बरामदगी उसे हेरोइन से नहीं जोड़ती है।
- (viii) अधिक दबाव में, उक्त विदेशी नागरिक (राजू दुबई) के खिलाफ कोई प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, और प्राथमिक अभिनेता जिन्होंने कथित रूप से खेपों पर वास्तविक नियंत्रण का प्रयोग किया, वे अभी भी फरार हैं।
- (ix) अपीलकर्ता का व्यवसाय दिल्ली स्थित है और वह 15 वर्षों से अधिक समय से आयात-निर्यात क्षेत्र में काम कर रहा है, और उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम या

यू. ए. पी. ए. के तहत कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है-इस प्रकार यह साबित होता है कि उसे भागने का जोखिम नहीं है;

(x) अपीलकर्ता 24.08.2022 के बाद से न्यायिक हिरासत में है, और लंबे समय तक निवारक निरोध उसके स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

22. इसके बिल्कुल विपरीत, गुजरात राज्य/एन. आई. ए. की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी अपीलकर्ता को जमानत देने के अनुरोध को मुखरता से चुनौती देना चाहती हैं। उस उद्देश्य के लिए, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का प्रचार किया:

(i) अपीलकर्ता केवल एक आनुषंगिक कर्ता नहीं था, बल्कि छह प्रमुख खेपों में से कुछ में एक प्रमुख सहायक था, जिसने सामूहिक रूप से भारतीय इतिहास में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के बाजार मूल्य के साथ बड़ी बरामदगी के रूप में मान्यता प्राप्त की है।

(ii) मेसर्स मैजेन्ट इंडिया सितंबर 2020 में राजू दुबई के साथ अपनी पहली बैठक के तुरंत बाद अपीलकर्ता द्वारा बनाई गई एक अग्रणी कंपनी थी। अपीलकर्ता के निर्देशों के तहत दिसंबर 2020 में आयातित खेप सितंबर 2021 में जब्त की गई बाद की खेप के साथ एक प्रत्यक्ष परिचालन पैटर्न साझा करती है; इस प्रकार, सभी छह खेपों में धोखाधड़ी के समान लक्षण थे और हेरोइन की तस्करी को छिपाने के लिए अफगान मूल के टैल्क का उपयोग करते हुए शेल फर्में के माध्यम से भेजे गए थे;

(iii) हालाँकि अपीलकर्ता की खेप से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं किया गया था, लेकिन शारीरिक वसूली की अनुपस्थिति में यू. ए. पी. ए. और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश के मामले के लिए घातक नहीं है-जो विदेशों में अपीलकर्ता की बैठकों, टेलीफोन कॉल, संरक्षित गवाहों द्वारा से कथित समन्वय, और दस्तावेजी ट्रेल्स को अस्पष्ट करने का प्रयास से निकला है।

(iv) जिस दिन एक प्रमुख गवाह को न्यायिक बयान दर्ज करना था, उस दिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु, इस तथ्य के अलावा कि दो महत्वपूर्ण गवाह अप्राप्य हैं, स्पष्ट रूप से गवाह के उन्मूलन या प्रभाव के जोखिम का संकेत देते हैं यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है;

(v) यह न्यायालय पहले ही समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर चुका है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो दो साल से अधिक समय से हिरासत में थे, इस आधार पर कि यू. ए. पी. ए. की धारा 43डी (5) की कठोरता को आकर्षित किया गया था। वर्तमान मामले में एक अलग निष्कर्ष

निकालने के लिए कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं दिखाई गई है, विशेष रूप से जब कई प्रमुख गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है, और कई आरोपी फरार हैं।

- (vi) तब से चल रहे मुकदमे में आरोप तय किए गए हैं, जिसमें कई प्रमुख गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा रही है- जो इंगित करता है कि मुकदमा उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा है।
- (vii) अपीलकर्ता एक आदतन आर्थिक अपराधी है, जिसका पूर्ववृत्त तस्करी और सीमा शुल्क उल्लंघन से संबंधित है, जो विषय-कानूनों की कठोरता को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के खिलाफ विद्रोह करता है; और
- (viii) अपीलकर्ता के विरुद्ध अभिकथित अपराधों की गंभीर प्रकृति और राष्ट्र की सुरक्षा पर उनके प्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव अनिवार्य रूप से यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलकर्ता को इस स्तर पर जमानत की राहत नहीं दी जानी चाहिए।

23. शुरुआत में यू. ए. पी. ए. की धारा 43 डी (5) के दायरे और आवेदन पर चर्चा करना उचित हो सकता है, जहां अदालत के तहत, जमानत के स्तर पर साक्ष्य की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रावधान के तहत आवश्यक संतुष्टि की मात्रा उचित संदेह से परे प्रमाण से कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी विषय-वस्तु में निहित होनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से असंभव या प्रत्यक्ष रूप से अविश्वसनीय न हो।

24. यू. ए. पी. ए. की धारा 43डी(5) की कठोरता, हालांकि, एक उपयुक्त मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश के अनुरूप होगी, विशेष रूप से जहां मुकदमे में अत्यधिक देरी होती है या जहां कारावास दंडात्मक हो जाता है। हालांकि, इस तरह की छूट संभवतः स्वचालित नहीं हो सकती है और प्रत्येक मामले से जुड़े विशिष्ट तथ्यों और जोखिमों के आलोक में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है।¹

25. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर और अभिलेख पर विषय-वस्तु के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर अपना चिंतित विचार देने के बाद, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता इस स्तर पर नियमित जमानत देने के लिए मामला बनाने में समर्थ नहीं है।

26. हम कहते हैं या इसका कारण यह है कि अपीलकर्ता से प्रतिबंधित पदार्थ की कोई प्रत्यक्ष बरामदगी नहीं होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसने मैसर्स मैजेन्ट इंडिया द्वारा टैल्क के रूप में छिपे हुए नशीले पदार्थों के आयात को सुविधाजनक बनाने में एक समन्वय और सक्षम भूमिका निभाई-जिसे उसने कथित रूप से एक प्रॉक्सी द्वारा नियंत्रित किया था। खेप, हालांकि हेरोइन के साथ जब्त नहीं की

गई थी, उन लोगों के साथ संरचनात्मक और रसद समानताएँ साझा करती है जहाँ अंततः हेरोइन पाई गई थी।

27. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप का मूल्यांकन तथ्यों के व्यापक मैट्रिक्स के आलोक में भी किया जाना चाहिए, जिसमें (i) दुबई में एक प्रमुख विदेशी अभियुक्त के साथ उसकी कथित बैठकें; (ii) एक चिह्नित खेप की मंजूरी के लिए बिचौलियों द्वारा से दस्तावेजों का हस्तांतरण; (iii) पूर्वव्यापी रूप से जाली चालान बनाने और दूसरों को जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास; (iv) लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करने के लिए कथित रूप से उससे जुड़ी कई फर्मों का उपयोग; और (v) कुछ सह-साजिशकर्ताओं को उसकी टेलीफोन कॉल शामिल हैं। संरक्षित गवाहों के बयानों और परिस्थितिजन्य संबंधों द्वारा समर्थित ये पहलू वर्तमान में अपीलकर्ता की मिलीभगत के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्टि की सीमा को पूरा करते हैं।
28. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि अपीलकर्ता से जुड़ी खेप से कोई नायक या मादक पदार्थ सीधे बरामद नहीं किए गए थे। हालाँकि, खोजी कथा केवल शारीरिक सुधार पर नहीं टिकी है, बल्कि साजिश और सुविधा के आधार पर आगे बढ़ती है। ऐसे मामलों में, प्रत्यक्ष बरामदगी का न होना निर्णायक नहीं होता, विशेष रूप से तब, जब गुप्त समन्वय, काल्पनिक/फर्जी संस्थाओं का उपयोग, तथा वस्तु-विनिमय आधारित प्रतिफल का एक स्पष्ट पैटर्न मौजूद हो— ये वे विशेषताएँ हैं जो अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्तमान मामले में अपनाई गई तस्करी की संरचना को चिह्नित करती हैं।
29. अपीलकर्ता गंभीर आरोपों का सामना करता है, जो कथित रूप से गंभीर सामाजिक प्रभाव डालते हैं, जिसमें सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी की सुविधा शामिल है—संगठित अपराध और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षरण के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित लिंक वाला अपराध। संबंधित खेप में जब्ती भारतीय इतिहास में हेरोइन का सबसे बड़ा भंडाफोड़ होने का दावा करता है, जिसका मूल्य 21,000 करोड़ रुपये से अधिक है। विदेशी सिंडिकेटों, शेल कंपनियों, मेडिकल वीज़ा और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी इस कार्रवाई का पैमाना और परिष्कृत स्वरूप, इस मामले को सामान्य एनडीपीएस उल्लंघनों से कहीं अधिक गंभीर स्तर पर ले जाता है।
30. यह न्यायालय इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि अभी भी कई प्रमुख गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है, और मुकदमे के दौरान, पूरा होने में समय लगेगा। 24 सबसे कमज़ोर या अहम गवाहों में से दो की मौत हो गई है, और दो अन्य का पता नहीं चल रहा है। मृतक गवाहों में से एक, एक सेवानिवृत्त सीमा शुल्क अधिकारी, उसी दिन मृत पाया गया था जिस दिन वह दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत अपना बयान दर्ज करने वाला था। गवाह के साथ छेड़छाड़ या उन्मूलन का जोखिम-चाहे वह सीधे अपीलकर्ता के लिए जिम्मेदार हो या नहीं—एक वास्तविक और

वर्तमान चिंता है जो इस स्तर पर जमानत देने के खिलाफ है।

31. इसके अलावा, अपीलकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि में, हालांकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत पूर्व आरोप शामिल नहीं हैं, कई डी. आर. आई. और सीमा शुल्क कार्यवाही शामिल हैं जिनमें सिगरेट की तस्करी, आयात का कम मूल्यांकन और भ्रष्टाचार के अपराधों में कथित संलिप्तता शामिल है। ये पूर्ववृत्तियां केवल जमानत पर विस्तारित होने पर न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अपीलकर्ता की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।
32. एन. आई. ए. ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि मुख्य विदेशी साजिशकर्ताओं सहित कई आरोपी फरार हैं। उस संदर्भ में, उड़ान जोखिम की संभावना का मूल्यांकन करने में अपीलकर्ता की विदेश यात्रा, विदेश संपर्क और वित्तीय क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये अटकलें नहीं हैं, बल्कि ये सीधे अपील करने वाले के पिछले व्यवहार और प्रोफाइल से जुड़ी हैं।
33. हम इस तय किए गए सिद्धांत से अवगत हैं कि मुकदमे से पहले कैद को दंडात्मक हिरासत में नहीं बदलना चाहिए। अपीलकर्ता 24.08.2022 से हिरासत में है, और हालांकि हमें नहीं लगता कि मौजूदा हालात में सिर्फ यह अवधि ही जमानत के लिए काफी है, फिर भी अपीलकर्ता छह महीने बाद या ट्रायल में काफी प्रगति होने पर, जो भी पहले हो, जमानत के लिए अपनी अर्जी दोबारा दे सकता है। इस तरह का पाठ्यक्रम अभियोजन को बाद में और अधिक उपयुक्त चरण में रिहाई की मांग करने के आरोपी के अधिकार को संरक्षित करते हुए अपने मुख्य गवाहों की जांच पूरी करने की अनुमति देगा।
34. इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि इस स्तर पर, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को आतंक के वित्तपोषण के क्षेत्र में विस्तारित करना जल्दबाजी और अटकलबाजी होगी। जबकि अभियोजन पक्ष ने यू. ए. पी. ए. के प्रावधानों को लागू किया है और व्यापक रूप से तस्करी उद्यम को संदिग्ध संबद्धता वाले अंतर-राष्ट्रीय सिंडिकेट्स से जोड़ा है, वर्तमान में अपीलकर्ता और देश के अंदर या बाहर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को जोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं है। इस तरह के गंभीर आरोप को बनाए रखने के लिए साक्ष्य आधार स्पष्ट और सम्मोहक होना चाहिए-कुछ ऐसा जो दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य के एक बड़े हिस्से के नेतृत्व के बाद ही देखा जा सकता है।
35. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ तत्काल अपील को खारिज करते हैं:
 - i. इस स्तर पर अपीलकर्ता को नियमित जमानत नहीं दी जा सकती। छह माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात्, अथवा उस अवस्था में जब चल रहा विचारण पर्याप्त

रूप से आगे बढ़ चुका हो, अपीलकर्ता नियमित जमानत हेतु अपनी प्रार्थना पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- ii. एनआईए को निर्देशित किया जाता है कि वह विशेष न्यायालय के समक्ष गवाहों की एक अतिरिक्त सूची प्रस्तुत करे, जिन्हें उसके आकलन में संवेदनशील अथवा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनकी साक्ष्य/गवाही का चल रहे विचारण तथा संबद्ध जांच में अपीलकर्ता अथवा अन्य सह-अभियुक्तों की भूमिका पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
 - iii. विशेष न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले को प्रति माह दो बार सूचीबद्ध करे तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान निरंतर एवं बिना किसी अवरोध के दर्ज करे।
 - iv. यदि अब तक विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्यवाही करें।
36. अत्यधिक सावधानी के तौर पर तथा पुनरुक्ति की सीमा तक, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश को प्रकरण के गुण-दोषों पर किसी भी प्रकार की राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा और न ही यह किसी भी प्रकार से विचारण की कार्यवाही को प्रभावित करेगा।
37. तदनुसार आदेश दिया गया। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।
- मामले का परिणाम: याचिका खारिज कर दी गई।

[†]हेड नोट्स तैयार किए गए: दिव्या पांडे